

महिला आरक्षण को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है सरकार

इस सोच के तहत संसद में तीन दिन का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, 16 से 18 अप्रैल को

—नेपू मित्तल—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। संसद के बजट सत्र में एक तीसरा विशेष सत्र देखने को मिलेगा, जिसे 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए बुलाया जाएगा, ताकि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा सके।

लोकसभा और राज्यसभा को आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थगित कर दिया गया, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं।

दोनों सदनों की 16 अप्रैल को फिर से बैठक होगी, जहां सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संशोधित विधेयक पेश करेगी।

महिलाओं को आरक्षण देने की अपनी मंशा का संकेत देने की जल्दबाजी में सरकार इसे परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना से जोड़ना चाहती है, जो अब पुरानी हो चुकी है

■ इस मकसद से सत्र में विशेष संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा। हालांकि, अभी सरकार के सांसदों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इस संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, पर फिर भी सरकार इस संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए अड़ी हुई है।

■ सरकार का मानना है कि अगर विधेयक पारित नहीं हुआ तो यह मैसैज तो जाएगा ही, कि सरकार महिला आरक्षण के पूर्णतया पक्ष में है। पर, विपक्ष सरकार के इस प्रयास को सफल नहीं होने दे रहा है।

■ क्योंकि, विपक्ष, इस दौरान विधानसभा चुनाव में व्यस्त होगा। अतः सरकार की सोच है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करने का पूरा नाटक वह आसानी से रच सकेगी।

और इसका कोई खास औचित्य नहीं माना जा रहा है।

अन्य संशोधन भी प्रस्तावित है,

लेकिन राजनीतिक दल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करना आसान नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं है।

भले ही यह पूरा मामला एक राजनीतिक नाटक साबित हो और विधेयक पारित न हो, पर सरकार यह प्रचार जारी रख सकती है कि वह विधेयक पास करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था।

यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।

इस बीच, विपक्षी दल विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और भाजपा इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

महिलाओं के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में तीन दिनों तक खींचतान और राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा।

एसआई भर्ती 2025 में 2021 के अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश

जयपुर, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े मामले में एसआई भर्ती, 2021 में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतिम राहत दी है। अदालत ने इन्हें अस्थाई तौर पर 5 व 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के

■ सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की एसआई भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को राहत दी।

परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे, जब तक संबंधित हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। जस्टिस दीपाकर दत्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सूरजमल मीणा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों को कहा है कि वे अदालती आदेश की कॉपी 4 अप्रैल तक परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराएं और वहां से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करें।

प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात जजों को नौ घंटे बंधक बनाकर रखा गया बंगाल के मालदा जिले में

ये जुडिशियल अफसर एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य कर रहे थे

—अंजन राय—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्य में अराजकता का माहौल व्याप्त है।

मालदा जिले के मोथाबाड़ी क्षेत्र में एक घटना सामने आई, जिसमें एसआईआर कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देर रात केन्द्रीय बलों की एक टुकड़ी ने मौके पर पहुंचकर इन अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप है कि ये घटनाएं उसी तरह हो रही हैं, जैसा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से करने का आ

■ सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की कि बंगाल में हर चीज का "राजनीतिकरण" हो चुका है। अतः सवाल यह उठ रहा है कि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश में बढ़ती अराजकता व हिंसा के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही।

■ ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से हिंसा प्रतिपादित कर रही हैं तथा कह रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने देंगे।

■ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन जुडिशियल अफसरों ने राज्य सरकार को और कोलकाता हाई कोर्ट को पहले ही सूचित कर दिया, अपनी सुरक्षा के बारे में, विशेषकर उस क्षेत्र में जहाँ कि सत्यापन का काम कर रहे थे।

■ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की भारी भर्त्सना की, इन जुडिशियल अफसरों को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करने के कारण। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अगर जुडिशियल अफसरों को ही सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती तो निष्पक्ष, निडर, चुनाव होने की संभावना की कल्पना ही व्यर्थ है।

कर रही है। बताया गया कि महिलाओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया

आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह लवली युनिवर्सिटी के चीफ अशोक मित्तल की नियुक्ति की है

—डॉ. सतीश मिश्रा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी लाइन का उल्लंघन करने के कारण राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक-चेयरमैन हैं।

गुरुवार को आप की ओर से राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा गया, जिसमें पार्टी के उपनेता पद के लिये पंजाब से निर्दिष्ट चुने गए मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया।

मित्तल ने मीडिया से कहा, "हमारी पार्टी में हर किसी को बोलने का समय मिलता है; यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राघव चड्ढा को भी भविष्य में राज्यसभा में बोलने का अवसर दिया जाएगा।"

आईपैक के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की रेड

बेंगलुरु, 02 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में चोटिंग से पहले एक बार फिर से आईपैक के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में यह कार्यवाही चल रही है। इससे पहले कोलकाता स्थित ऑफिस में ईडी की रेड हुई थी। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल

■ आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव प्रबंधन संभाल रही है और यह रेड कोयला तस्करी के मामले में की जा रही है।

को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थीं। इस दौरान खूब सियासी बवाल हुआ था।

दरअसल, ईडी की यह छापेमारी कोयले की तस्करी को लेकर चल रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में चल रही है। आईपैक पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रबंधन का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को पत्र भेजकर मित्तल की नियुक्ति की सूचना दी गई तथा पत्र में राघव चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखने का आग्रह भी किया गया है।

■ आप नेतृत्व का आरोप है कि राघव काफी समय से पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे थे, पार्टी के वॉकआउट के समय भी वे सदन में बैठे रहते थे, यही नहीं उन्होंने पार्टी नेतृत्व से भी दूरी बना ली है।

■ चर्चा है कि राघव भाजपा नेतृत्व के सम्पर्क में भी हैं। इसलिए आप ने पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली युनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिया है।

आप ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी अनुरोध किया है कि चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखा जाए। सूत्रों के अनुसार, 37 वर्षीय चड्ढा पिछले कुछ महीनों में कई बार सदन में

पार्टी लाइन के खिलाफ जाते रहे हैं।

12 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिस पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वृद्धा से 80 लाख की साइबर ठगी करने वाले की अग्रिम जमानत से इंकार

जयपुर, 2 अप्रैल (निर्स)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर की 83 साल की वृद्धा को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 80 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश नवीन टेमानी की ओर से

■ हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जो समझौते से सुलझाया जा सके।

दायर द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसे समझौते से सुलझाया जा सकता है, बल्कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गंभीर अपराध है, अदालत ने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'5037 बीघा में कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण है, नक्शा बनाकर पेश करो'

हाई कोर्ट में 5037 बीघा ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया

—कार्यालय संवाददाता—

जयपुर, 2 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर में अवाप्त की जा रही 5037 बीघा जमीन में से काफी बड़े हिस्से पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में 'पब्लिक अग्रेसट करप्शन' नामक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश पुष्पेन्द्र पाटी और पुनीत कुमार माथुर ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ए.एस.जी.) के आश्विन को मद्देनजर रखते हुए आदेश दिये हैं कि राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि एक भूखंड में शेष खुले स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होने दिये जायेंगा। अदालत ने आदेश में आगे कहा कि हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता के वकील पूरे क्षेत्र का विस्तृत मैप बनायें, जिसमें विवादित क्षेत्र और खुले क्षेत्रों को अच्छे से अंकित किया गया हो, ताकि अतिक्रमण होने से रोका जा सके।

■ याचिकाकर्ता, "पब्लिक अग्रेसट करप्शन" ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि 12 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही है, 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद, इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

■ हाउसिंग बोर्ड ने कहा, कुल अवाप्त 5037 बीघा जमीन पर कुल जरूरतमंदों ने कब्जा कर रखा है।

अदालत ने इस दस्तावेज को बनाने व अदालत में पेश करने के लिये हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता को समय दिया है और इस मामले की अगली तारीख 1 मई, 2026 तय की है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका यह कहते हुए दायर की गई है कि 12 मार्च 2025

को अदालत ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान

इस मामले में आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान

एएसजी भरत व्यास की ओर से कहा गया है कि 5037 बीघा में से 4000 बीघा जमीन हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की जा चुकी है और उसका कब्जा है। शेष भूमि पर कई जगह अतिक्रमण हैं, परंतु वह इसलिए हैं कि जयपुर में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है और बाहर से आये लोगों को शहर में बसाने के लिये गैरकानूनी कॉलोनियां काटी गईं। उन्होंने कहा कि शहरीकरण रोकना अत्यंत ही मुश्किल काम है। हालांकि गैरकानूनी सोसायटी काटने से सुनियोजित विकास नहीं किया जा सकता है, परंतु राज्य सरकारों को शहर के बाहर से आये गरीबों और रोजगार की खोज में आये लोगों की आवश्यकताओं को भी देखना जरूरी है। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से इस मुद्दे पर संवेदनशील करना चाहा कि अतिक्रमण हटाने से कई गरीबों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस मामले की सुनवाई के दौरान

इस मामले की सुनवाई के दौरान

अदालती आदेश के बावजूद चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाने पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये

■ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी स्वायत्तशासी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जायें।

■ परंतु अदालती आदेशों के बावजूद मुख्य निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी करे, जिसके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और फिर उसका अंतिम प्रकाशन होगा और चुनाव उसके बाद ही हो सकेगा।

अदालत ने इसकी न तो कोई अनुमति दी है, और न ही अदालत से अनुमति मांगी गई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी पैरवी

के लिये प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी

2026 तक प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जायें। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिये थे कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी

कर ली जाये। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि चुनाव आयोजित नहीं कराने की वजह से कई निकाय गैरकानूनी तरीके से अपने कार्यकाल से डेढ़ से दो वर्ष अधिक से कार्यरत हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं आयोजित होने की वजह से आम जनता के वोट डालने के संविधानिक हक को छीना जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने आदेश दिये थे कि 15 फरवरी तक चुनाव करा दिये जायें।

पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि अदालती आदेशों के बावजूद, निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी किये, जिनके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और उसका अंतिम प्रकाशन हो जायेगा। उन्होंने अदालत को कहा कि ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक चुनाव आयोजित कराने के आदेश की पालना असंभव है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और टिप्पणी की कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईआरजीसी कमांडर फतह अलीजादेह की मौत

तेहरान, 02 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच ईरान को एक और झटका लगा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की बेहद खतरनाक मानी जाने वाली फतेहिन स्पेशल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली फतह

■ ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान हुई।

अलीजादेह की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान हुई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अलवर और अजमेर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली

पासपोर्ट कार्यालयों को खाली करवाकर बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियों ने जांच की

अलवर/अजमेर, (निर्स)। अलवर में पासपोर्ट कार्यालयों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई। धमकी भरे संदेश में दोपहर दो बजे ब्लास्ट होने की बात लिखी गई, जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन सभी कर्मचारियों और आम लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया। मौके पर सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरे क्षेत्र को घेर लिया।

जानकारी के अनुसार अलवर पासपोर्ट ऑफिस को इस महिने में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी दो बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे ऑफिस को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मुख्य गेट को बंद कर किसी भी व्यक्ति की एंट्री पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में यह दूसरी बार है, जब इस तरह की धमकी मिली है। ई-मेल के जरिए भेजी गई इस धमकी में राजस्थान के कई पासपोर्ट कार्यालयों को निशाना बनाने की बात कही गई है। मेल में लिखा गया कि दोपहर दो बजे से पहले ऑफिस खाली कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद बम विस्फोट किया जाएगा। साथ ही धमकी देने वाले ने कर्नाटक की राजनीति से जुड़े किसी मुद्दे का भी जिक्र किया है।



भरतपुर में करोड़ों की ठगी मामले में

इस दौरान पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों को भीड़ जमा हो गई, जो अपने काम के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने सभी लोगों को गेट के बाहर ही रोक दिया और स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करने के लिए कहा।

कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश ने बताया कि फिलहाल पूरे परिसर की बारीकी से जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल ऑफिस का कामकाज भी रोक दिया गया है।

अजमेर संवाददाता के अनुसार :- पासपोर्ट मुख्यालय जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को एक धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद अजमेर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में हड़कंप मच गया। ई-मेल में कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी गई।

■ अलवर और अजमेर पासपोर्ट ऑफिस में तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली

■ पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है और साइबर टीम को मदद से मामले की गहन जांच की जा रही है

आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियों द्वारा पूरे कार्यालय परिसर को बारीकी से जांच की गई। करीब लंबे समय तक चली तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है और साइबर टीम को मदद से मामले की गहन जांच की जा रही है।

बीकानेर से खाड़ी देशों को जाने वाला 100 कंटेनर माल का निर्यात ठप

बीकानेर, (निर्स)। खाड़ी देशों में सालाना 50 हजार टन बीकानेरी भुजिया समेत अन्य आइटम जाते हैं, लेकिन युद्ध के कारण करीब 100 कंटेनर निर्यात ठप हो गया है। एक कंटेनर में 25 टन माल आता है। दुबई व अन्य देशों में कंटेनर फंस गए हैं। दुबई के क्रूज टर्मिनल पोर्ट राशिद बंदरगाह पर कंटेनर का किराया भी 120 डॉलर से बढ़कर 2200 डॉलर तक पहुंच गया है।

■ दुबई के क्रूज टर्मिनल पोर्ट राशिद बंदरगाह पर कंटेनर का किराया भी 120 डॉलर से बढ़कर 2200 डॉलर तक पहुंचा

■ 'हर महिने 15 से 20 कंटेनर भुजिया, पापड़ और नमकीन का एक्सपोर्ट होता है, जो फिलहाल बंद है'

इसके अलावा अन्य देशों में हर महिने करीब 80 कंटेनर माल भेजा जाता है, वो भी अटका हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही हालात रहे तो भुजिया, पापड़ की कीमतों में 3 रुपये प्रति किलो का उछाल आ सकता है। अभी नमकीन उत्पादन पर

असर नहीं है। वहीं, नोखा के प्रमुख एक्सपोर्टर राजेश कुमार डंबर ने बताया कि हमने 850 डॉलर में कंटेनर किराए पर लेकर जीरा, मेथी दाना, मूंगफली दाना इराक भेजे थे, लेकिन माल बीच में ही कहीं

उतार दिया गया। अब शिपिंग कंपनी वॉर चार्ज के नाम पर 4 हजार डॉलर मांग रही है। युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में ऊन के कंटेनर अटक गए हैं।

ऊन व्यवसायी ऋषभ बोथरा ने बताया कि बीकानेर में 700-800 कंटेनर ऊन मीडिल ईस्ट से आता है। 11 मार्च को कुछ कंटेनर पहुंचे हैं, जो हीर्मुज पर फंसे हुए थे। अभी भी काफी कंटेनर बीच में ही अटके हुए हैं। वॉर चार्ज के नाम पर शिपिंग कंपनियों काफी पैसा मांग रही है। उन्होंने बताया कि युद्ध की वजह से बीकानेर का कारपेट उद्योग भी प्रभावित हुआ है।

पति ने पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंका, थाने पहुंचकर सरेंडर किया

हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, आरोपी पति हरप्रीत हिरासत में

बीकानेर, (निर्स)। एक पति ने पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया। इतना ही नहीं मर्डर के दो घंटे बाद थाने पहुंचा और सरेंडर कर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मामला जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में गुरुवार का है। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन, पुलिस ने आरोपी पति हरप्रीत को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के अनुसार दो अप्रैल को

■ प्रारंभिक जानकारी में आपसी विवाद के चलते ही पति के पत्नी की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है

दोपहर करीब 1:15 बजे हरप्रीत सिंह निवासी 8 डीडब्ल्यूडी थाना दंतौर, खाजूवाला थाने पहुंचा। यहां बताया कि उसने अपनी पत्नी जसवंत कोर की हत्या कर दी है। आरोपी ने बताया कि पत्नी का शव चक 9 डीडब्ल्यूडी के एक खेत

में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो जसवीर का शव झाड़ियों के बीच पड़ा था। इसके बाद एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और घटनास्थल से सबूत शामिल किए।

चौधरी व थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत बीकानेर में महानिदेशक पुलिस की संभागा स्तरीय बैठक में गए हुए थे। सूचना मिलने के बाद दोनों अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी में आपसी विवाद के चलते ही पति के पत्नी की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है।

घटना के समय डिप्टी अमरजीत

डार्क जोन में चल रही वाटर कंपनी को फिर मिला कोर्ट का नोटिस

अलवर, (निर्स)। अवैध रूप से अलवर के डार्क जोन आलापुर गांव में चल रही एक्वाफिल वाटर फैक्ट्री को कोर्ट नोटिस तामील नहीं करने पर दूसरा नोटिस जारी किया है और कंपनी को 28 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। अगर कंपनी संचालक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट एक तरफ फैसला सुना सकती है जबकि इसी संदर्भ में जिला कलैक्टर को मिले सम्मन की तामील होने के कारण उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है।

जिले की माचडी पंचायत समिति के अलापुर गांव में ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अपने रसूख पर चल रही एक्वाफिल वाटर फिल्टर कंपनी और जिला कलैक्टर को न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं, जिसकी पेशी 28 मार्च को था। गौरतलब है कि अलापुर गांव डार्क

■ आलापुर गांव में चल रही कंपनी के संचालक को 28 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया

जोन में है, यहा पानी की हमेशा से समस्या बनी हुई है। वहीं खसरा नम्बर 1128-613 और खसरा संख्या 1130-614 की जमीन पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक्वाफील्स टैड्स प्रा.लि. ने पानी फिल्टर करने की कंपनी लगा दी जिसका वहां के ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन उनके विरोध पर जिला प्रशासन ने कोई सजा नहीं लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वे दो बार जिला कलैक्टर से भी इस विषय पर मिले कि अगर यह कंपनी यहां बनी तो हमारा सारा पानी सौख लेगी, लेकिन ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की, आखिर में ग्रामीणों ने अदालत की शरण ली।

ग्रामीणों ने एक वाद समाजसेवी

जसवंत सिंह बगैरह ने सविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट- 2 की अदालत में दायर की वाद पर न्यायालय ने एक्वाफील्स कंपनी और जिला कलैक्टर को नोटिस जारी किए हैं।

समाजसेवी जसवंत यादव ने बताया है कि अलापुर डार्क जोन में आता है यहां पीने के पानी तक की समस्या है। ऐसे में इस कंपनी के लग जाने से कृषि प्रभावित हो रही है क्योंकि यहां लगे दर्जनों पंप रोजाना जमीन से जल का दोहन कर रहे हैं जिससे हमारे खेतों में लगे पंपों का पानी सूखने लगा है, अगर समय रहते सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं की तो ग्रामीणों को यहां से पलायन करना पड़ सकता है।

तस्करी में वांटेड 25 हजार इनामी अपराधी गिरफ्तार

जोधपुर, (कांस)। कमिश्नरेट जिला पश्चिम में ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को डीएसटी वेस्ट में जीआरपी थाने में वांटेड 25 हजार के इनामी आरोपी को पकड़ा है। वह पांच साल से मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में राजकीय रेलवे पुलिस का वांटेड था। उसे अब जीआरपी को सौंपा गया है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि जिला पश्चिम की तरफ से ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जिला पश्चिम की डीएसटी प्रभारी एसआई महेंद्र सिंह

प्रतिबंध के बावजूद राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए

उदयपुर, (कांस)। नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने के कारण सूरजपोल थाना एवं भूपालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु कई बार अपील के साथ सख्त कार्रवाई की गई है, लेकिन निगम द्वारा की

गई अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए गए, जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। शहर के दुर्गा नर्सरी, टी आर आई तिराहा, कुम्हारों का भट्टा पुलिया के नीचे, फल स्कूल दीवार, सूरजपोल के पास स्मार्ट कंयूटर्स आनंद प्लाजा द्वारा पोस्टर चिपकाये हुए थे। इसको लेकर पोस्टर चप्सा करने वाले के खिलाफ शहर के दो थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

शादी का झांसा देकर पांच लाख की ठगी

हनुमानगढ़, (निर्स)। भादरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर ठगी का एक मामला सामने आया है। एक युवक से विवाह के नाम पर लगभग पांच लाख रूपए नकद और सोने-चांदी के जेवर हड़प लिए गए। बाद में महिला घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पुलिस ने महिला सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को रासलाना निवासी वीर सिंह ने शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में जयवीर और उसके पिता बलवंत सहू, जो नुवा, गोवामेडी के निवासी हैं, ने उनकी शादी कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने भादरा निवासी स्वाती नामक युवती से विवाह कराने के लिए खर्च और 3 लाख

रूपए की शर्त रखी। आरोपियों ने रिश्तेदारी का हवाला देकर वीर सिंह का भरोसा जीता, जिस पर वह सहमत हो गए। शिकायत के मुताबिक, 26 जनवरी 2025 को आरोपी जयवीर और बलवंत एक युवती को लेकर रासलाना पहुंचे। परिवारजनों की मौजूदगी में स्वाती का विवाह वीर सिंह से करवा दिया गया। विवाह के बाद वीर सिंह ने स्वाती को सोने की चेन, चांदी की बिछिया और पायजेब दी। इसके अलावा 50 हजार रूपए खर्च के तौर पर और लगभग 2 लाख रूपए बिचौलिया शुल्क के रूप में आरोपियों को दिए गए।

पीड़ित वीर सिंह के अनुसार, शादी के बाद स्वाती उसकी पत्नी के रूप में रहने लगी और घर-परिवार संभालने का भरोसा दिलाया। हालांकि, 22 मार्च

2026 को जब परिवार के लोग खेत में काम करने गए हुए थे, तब घर पर केवल वीर सिंह की बुजुर्ग माँ और स्वाती मौजूद थी। वीर सिंह ने आरोप लगाया कि इसी दौरान स्वाती उसकी माँ के पास रखे लगभग 10 तोला सोने के जेवर और 2 लाख रूपए नकद लेकर फरार हो गई। जब वीर सिंह ने जयवीर और बलवंत से संपर्क किया, तो उन्होंने धमकी दी कि यदि कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इसके बाद पीड़ित वीर सिंह ने भादरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। भादरा पुलिस ने परिवारी वीर सिंह को शिकायत पर जयवीर, बलवंत और स्वाती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच एसआई राजेंद्र सिंह को सौंपी गई है।

मुंहबोली बहन से दुष्कर्म, दस दिन तक बंधक बनाया

श्रीगंगानगर, (निर्स)। महिला को काम के बहाने श्रीगंगानगर लेकर जाकर रेप करने का मामला सामने आया है। महिला को 10 दिन तक बंधक बनाकर भी रखा। महिला ने कहा कि आरोपी उसे मुंहबोली बहन कहता था और इसी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले गया।

आरोपी ने उसका फोन तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी किसी से बात नहीं हो पाई। किसी तरह उसके हाथ आरोपी युवक का फोन लगा, तो उसने अपने पति को कॉल कर आपबीती बताई। इसके बाद पति, देवर और ससुर उसे लेने के लिए राजस्थान पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही आरोपी श्रीगंगानगर में महिला को छोड़कर भाग गया। इसके बाद उसे यहां लाकर अस्पताल में मेडिकल के लिए

दाखिल करवाया। वहीं पति ने कहा कि उसने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब फिर से उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली 23 वर्षीय महिला अपने पति के साथ गांव में मजदूरी करती है और उसका एक बेटा भी है। महिला के अनुसार, गांव का ही मंगल सिंह नाम का युवक, जो किन्नू के बागों में काम करता है और उसे बहन कहता था, 23 मार्च को उसे मजदूरी के बहाने अपने साथ ले गया।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसे श्रीगंगानगर, जयपुर, बीकानेर और हरिद्वार ले गया। बाद में वह उसे वापस श्रीगंगानगर में अपने दोस्त प्रवीण के घर

छोड़ दिया। इस दौरान आरोपी ने लगातार उसके साथ मारपीट की और रेप किया। करीब 10 दिन तक बंधक बना कर रखा। महिला ने आरोप लगाया कि जाते समय आरोपी उसकी सोने की बाली और पायल भी अपने साथ ले गया और उसका फोन तोड़ दिया, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। करीब एक सप्ताह बाद आरोपी उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया।

थाना खुशियाँ के प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच लेडी इस्पेक्टर परमिला और गुरदीप सिंह को सौंप दी गई है। पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

महिला सुरक्षा, सायबर अपराध और नशे पर लगाम लगाने पर हमारा फोकस है : डीजीपी

बीकानेर, (निर्स)। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने गुरुवार को अपने दो दिवसीय दौर में अनेक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी निभाई। उन्होंने अश्व बल शाखा, सीसीटीएनएस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस लाइन का निरीक्षण किया

■ पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बीकानेर में पुलिस लाइन में मैसे व मोटर शाखा का निरीक्षण किया

■ पुलिस कार्मिकों के दपत्तर या थाने में व्यवहार को लेकर शिकायत आना बहुत गंभीर है : डीजीपी राजीव शर्मा



डीजीपी राजीव शर्मा ने मेस में जवानों को मिलकर डाइट के बारे में पूछा।

और सभी कक्षाओं और संघातिर दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के साथ एडीजी क्राइम विपिन पांडे, आईजी ओमप्रकाश, डीआईजी कुंवर राष्द्रीय, एसपी मृदुल कच्छवा सहित अनेक पुलिस अधिकारी थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षाओं, रिर्कांड्स और व्यवस्थाओं की गहन जांच की तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। डीजीपी ने पुलिस लाइन मेस और मोटर शाखा का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेस में जवानों को मिलने वाली डाइट के बारे में पूछा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके

अलावा बहनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं को लेकर भी जानकारी ली। इस अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन किया गया।

मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि पुलिस कार्मिकों के दपत्तर या थाने में व्यवहार को लेकर शिकायत आना बहुत गंभीर है। गलत व्यवहार जनता के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान को पुलिसिंग में मॉडल स्टेट बनाना है। थाना पुलिसिंग की पहली इकाई है। थाने नागरिकों के अनुकूल हों। नागरिक, गरिमा और न्याय पहले थानों का आदर्श वाक्य होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं

और बच्चियों की सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा। इसके लिये स्कूल स्तर पर महिला सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज के बदलते दौर में तकनीक पुलिस की मजबूत साथी होगी। आधुनिक निगरानी प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सेवा को बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास होगा। डीजीपी ने शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में जवानों की पदोन्नति के मामले में पेंडिंग चल रहे थे। उन जिलों के अधिकारियों को जल्द पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए। साथ ही पेंडेंसी कम करने के

आदेश दिए। डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस के हाल ही में किए डिवाय ऑपरेशन पर कहा कि हर गलत चीज के प्रति हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे पर लगाम लगाना हमारा सीधा फोकस है। बीकानेर सीमावर्ती इलाका होने के कारण सतर्कता अधिक बरती जाएगी। राज्य सरकार का भी यही ध्येय है कि आम पुलिस को लगातार ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होती है। डीजीपी राजीव शर्मा ने बीकानेर प्रवास के दौरान संपर्क सभा में साधियों को बताया है कि आम आदमी के साथ हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए।

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिये एसआईसीसी की स्थापना होगी

जयपुर। राज्य सरकार के कौशल, नियोजन एवं उद्यमता विभाग द्वारा युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। यह पहल भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतरराष्ट्रीय माजारों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें वैश्विक जाब मार्केट के लिए सक्षम बनाना है।

जयपुर में उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान/आईटीआई तथा आईटी एवं मैनेजमेंट संस्थानों की उपलब्धता के साथ-साथ प्रशिक्षित एवं शिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद है, जो वैश्विक रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एसआईसीसी की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगा। इस हेतु जयपुर स्थित महात्मा गांधी शासन एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान (जेएलएनएम) की उपलब्ध आधोसंरचना का उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा 16 मार्च को प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया जा



भरतपुर कलैक्टर ने मौका मुआयना कर कुम्हरे में दो उपयुक्त स्थलों का चयन किया।

चुका है तथा उनकी रिपोर्ट कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। केंद्र में मोदी सरकार के अनुमोदन उपरांत जयपुर में यह केंद्र इसी माह में स्थापित किये जाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

वहीं जयपुर में एसआईसीसी स्थापना में भोजनलान संस्कार की त्वरित कार्रवाई से प्रभावित होकर भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य का दूसरा एसआईसीसी भरतपुर में स्थापित

किये जाने का संकेत दिया है। इस हेतु भरतपुर जिला कलैक्टर कमर उल जमान चौधरी द्वारा दो अप्रैल को मौका मुआयना कर कुम्हरे में दो उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है तथा केंद्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत यह केंद्र मई 2026 तक प्रारम्भ होने की संभावना है।

माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राज्य के 17 लाख युवाओं का पंजीयन- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म के तहत प्रदेश में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की

जयपुर, 2 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए। "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" देश की इसी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का सशक्त माध्यम बन रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में 17 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को अवसर देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकथाम के लिये नशा-मुक्ति की दिशा में भी गतिविधियाँ संचालित की जाएँ।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशा मुक्ति, फिटनेस और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा की।

"फिट राजस्थान, हिट राजस्थान" के विजन को हर गांव और शहर तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पेरपलीक और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं से युवाओं के सपनों पर कुटाराघात हुआ। अब भर्ती परीक्षाएँ पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी

के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियों दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है। बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" युवाओं को सरकार से सीधे जोड़ने का सशक्त डिजिटल

माध्यम है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएँ, नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंडटेबल और माय भारत बजट क्वेस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से युवा अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, जिससे विकसित

अदालती आदेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आयोग अपने आप ही चुनाव के कार्यक्रम को 15 तारीख से आगे बढ़ाने का फैसला कैसे ले सकता है, जबकि इस संदर्भ में न तो अदालत में कोई आवेदन पेश किया गया है और न ही अदालत ने कोई अनुमति दी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाअधिवक्ता को भी अदालत में उपस्थित होने का आग्रह किया। महाअधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार कुछ ही दिनों में चुनाव के कार्यक्रम को 15 अप्रैल से आगे बढ़ाने के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत करने जा रही थी। परंतु आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम कैसे और किस प्रकार से तय

किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में अदालत के समक्ष ऐसा कोई भी आवेदन पेश नहीं किया गया है। अदालत ने आगे कहा कि प्रदेश के चुनाव आयोग को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव स्वतः ही आगे कैसे बढ़ाया, जबकि अदालती आदेश इसके बिल्कुल विपरीत थे। इसके साथ ही, अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करा है।

आईआरजीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के दौरान हुई। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिगेडियर जनरल फतह अलीजादेह की जान दुश्मनों के हवाई हमले में गई है। मोहम्मद अली फतह अलीजादेह कोई साधारण फौजी नहीं थे। वे आईआरजीसी की उस स्पेशल वॉलेंटियर यूनिट की कमान संभाल रहे थे, जो गुरिल्ला युद्ध और बेहद कठिन ऑपरेशंस

को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। इस यूनिट को सीधे तौर पर फतेहिन कहा जाता है। सीरिया के गृहयुद्ध में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार को बचाने और आतंकियों से लोहा लेने के लिए इसी फतेहिन यूनिट को मैदान में उतारा गया था। फतह अलीजादेह जैसे अनुभवी कमांडर का मारा जाना ईरानी के लिए बड़ा क्षति है।

मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ब्रिज पर अमेरिका का हमला

तेहरान, 02 अप्रैल। ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाले एक 'बी1 हाईवे ब्रिज' पर गुरुवार को हवाई हमला किया गया। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और आसपास के इलाकों में भी नुकसान हुआ है।

यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबा और

■ **3800 करोड़ रु. की लागत से बना यह पुल तेहरान को ईरान के उत्तरी भाग से जोड़ता है।**

136 मीटर ऊंचे पिलर वाला यह प्रोजेक्ट करीब 400 मिलियन डॉलर में बना था।

इस कूटनीतिक पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय सरकार सहमत और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। शर्मा का यह बयान अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रुख से अलग है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस इस युद्ध के दौरान

■ **केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण में बताया कि भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएँ, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंडटेबल और माय भारत बजट क्वेस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन व कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर आयोजित होते हैं।**

भारत के विजन को गति मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बने विकसित भारत यंग लीडर्स से संवाद भी किया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण एवं यंग लीडर्स उपस्थित थे।

पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने भारत की कूटनीति को सराहा

इससे पहले शशि थरुर भी भारतीय नीति की सराहना कर चुके हैं

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। शशि थरुर के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया के ताजा संकट में भारत की कूटनीति को परिपक्व और कुशल बताते हुए कहा है कि इसने संभावित खतरों से सफलतापूर्वक बचाव किया है। इस कूटनीतिक पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय सरकार सहमत और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। शर्मा का यह बयान अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रुख से अलग है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस इस युद्ध के दौरान

■ **इसके विपरीत कांग्रेस नेतृत्व लगातार भारतीय कूटनीति का विरोध कर रहा है।**

■ **एक अन्य नेता कमलनाथ ने भी कहा कि एलपीजी संकट नहीं है।**

भारत की कोई कूटनीतिक भूमिका नहीं होने से लेकर, एलपीजी रसाई गैस, डीजल-पेट्रोल की कमी होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की आलोचना करते रहे हैं। रोकथम तथ्य यह है कि पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता कमलनाथ ने भी एलपीजी की किस्मत को केवल अटकल बताया और कहा कि कोई कमी नहीं है। गुरुवार को आनंद शर्मा ने एक बयान में कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के अनुचित हमले के बाद

दुनिया भर में उथल-पुथल मच गई है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है।

शर्मा ने कहा कि भारत के खाड़ी देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं और ईरान से सभ्यतागत रिश्ते हैं। पेट्रोलियम, एलपीजी और पीएनजी जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तियों और 200 अरब डॉलर के व्यापार के अलावा, एक करोड़ से ज्यादा भारतीय प्रवासियों के हितों की सुरक्षा के साथ लगभग 60 प्रतिशत

विदेशी मुद्रा के आने के साधन का भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस संकट से निपटने में भारत की कूटनीति काफी परिपक्व और कुशल रही है, जिसने संभावित खतरों से सफलतापूर्वक बचाव किया है।

अपने बयान को सही ठहराते हुए बातचीत में कहा कि उन्होंने सरकार के संदर्भ में नहीं, भारत की कूटनीति की कुशलता की बात की है, जिसमें हमारे राजनयिकों की बड़ी भूमिका है। पश्चिम एशिया संकट पर संवर्द्धलीय बैठक बुलाने की सरकार की पहल को सही ठहराते हुए शर्मा ने कहा कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आम सहमति और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए।

होर्मुज़ स्ट्रेट पर ब्रिटेन में 60 देशों की मीटिंग

भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहल पर करीब 60 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑनलाइन तरीके से होर्मुज़ संकट पर गुरुवार को चर्चा की। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेत कूपर ने की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था। मिसरी ने चर्चालु माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दुनिया भर के देशों के

■ **भारत ने मीटिंग में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत इकलौता देश है जिसने अपने जांबाज नाविकों को खोया है।**

सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बरोकटोक आवाजाही हर देश का हक है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश मंत्री के ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था। मिसरी ने चर्चालु माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दुनिया भर के देशों के

अपने जांबाज नाविकों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल और अधिक युद्ध नहीं है। अगर दुनिया को इस संकट से बाहर निकलना है, तो सभी पक्षों को तुरंत हथियारों को शांत कर बातचीत की मेज पर लौटना होगा। वहीं, बैठक के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, होर्मुज़ से जहाजरानी सेवाओं को फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा और इसके लिए समुद्री उद्योग साझेदारी के अलावा, सैन्य शक्ति और राजनयिक

गतिविधियों का एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक होगा। स्टार्मर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उस अपनी को स्पष्ट नकार चुके हैं कि ब्रिटेन व यूरोप के अन्य देशों को होर्मुज़ खुलवाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी दी कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य को आवागमन का मुद्दा ईरान युद्ध का ही परिणाम है और जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जलडमरूमध्य स्थिर नहीं रहेगा। वांग यी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने शीघ्र युद्धविराम का भी आन दिया।

ऑस्ट्रिया ने भी अमेरिका को एयरस्पेस देने से इन्कार किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ईरान और यूएस-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, कई देश युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में अमेरिका को झटका लगा है। अब ऑस्ट्रिया ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है।

ऑस्ट्रिया ने ईरान से जुड़े सैन्य ऑपरेशनों के लिए अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की अमेरिकी मांग टुकारा दी है। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला देश के सख्त तटस्थता कानून के तहत लिया गया है।

ट्रंप ने अमेरिकी जनता से कहा, हम जीत गए हैं

अमेरिका की जनता को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान को नष्ट करने का दावा किया

वॉशिंगटन, 02 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध पर देश को संबोधित किया है। भारतीय समयानुसार, गुरुवार सुबह साढ़े छह बजे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान सफल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज ने बहुत कामयाबी के साथ ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म करते हुए उनकी परमाणु हथियार हासिल करने की उम्मीद को खत्म किया है। उन्होंने ईरान में अमेरिका के लक्ष्य पूरे होने का ऐलान

■ **ट्रंप ने कहा कि ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है।**

किया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन एफिक फ्यूरी के तहत युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त

जीत हासिल की है। यह एक ऐसी जीत है, जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है। उनकी हथियारों की फैक्टरियां तथा रॉकेट लॉन्चर टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे रह गए हैं।

सात जजों को नौ घंटे बंधक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के एक समूह ने न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जो एसआईआर से संबंधित जरूरी कार्य कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हर चीज "राजनीतिक" हो चुकी है, जिसके कारण प्रशासन पर से लीगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। सवाल यह है कि राज्य में बढ़ती अराजकता और हमलों के बावजूद केन्द्र सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। निकट क्विस्म की हिंसा की इन घटनाओं के बावजूद, आरोप है कि ममता बनर्जी खुले मंचों से और उकसाने वाले बयान दे रही हैं। उन्होंने कांग्रेस, ओबेसी, माकपा तथा भाजपा पर इन घटनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। बताया गया कि उन्होंने लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, से अपील की कि जो भी उनके पास उपलब्ध हो, उसके साथ बाहर निकलें और एसआईआर

कार्य को रोकें। उन्होंने यह भी कहा कि "हमारी माताएं और बहनें चुप क्यों हैं?" और वादा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी हर कदम पर गैर-जिम्मेदारी और उकसाने की राजनीति को बढ़ाती रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर वे नहीं होतीं, तो बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) जीवित नहीं रहता। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनके बिना, यह समुदाय दूसरे समुदाय के हमलों का शिकार हो सकता है। इसके बाद से वे किसी भी कीमत पर एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) कार्य को रोकने के लिए संगठित प्रयास करती नजर आई हैं। राज्य के शीर्ष राजनीतिक स्तर से दिए गए ऐसे बयानों के बाद लोगों में उत्कराव का माहौल बन गया है।

चार न्यायिक अधिकारी एसआईआर के तहत मतदाता सूची सुधार का काम कर रहे थे। इन

अधिकारियों को भीड़ ने उनके कार्यालय में घेरकर रोक लिया, जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के आन के अंशुकूप ही हुआ। इन न्यायिक अधिकारियों ने पहले ही राज्य प्रशासन और कलकत्ता उच्च न्यायालय को उस क्षेत्र में अपनी असुरक्षा के बारे में सूचित किया था, जहां वे कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यस्थल को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उनकी मांग को राज्य प्रशासन तक ठीक से पहुंचाया ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं राज्य प्रशासन को सुरक्षा देने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि न्यायिक अधिकारियों को ही सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। पूरा कार्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किया जा रहा है।

आप ने राघव चड्ढा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
लोकसभा के 128 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, तब पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा ने कथित तौर पर उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। सुत्रों का कहना है कि कई मौकों पर चड्ढा सदन में बने रहे, जबकि आप सहित, विपक्ष के अन्य सदस्य वॉकआउट कर गए थे। वर्ष 2025 के दिल्ली चुनावों में आप की हार के बाद चड्ढा ने पार्टी के भीतर तो लो प्रोफाइल रखा और केवल व्यापक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित रखा था। बताया जाता है कि चड्ढा ने आप संस्थापक अरविन्द केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिंसोदिया के कथित शराब घोटाले में बरी होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाल ही में केजरीवाल द्वारा भाजपा के खिलाफ संबोधित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा में भी वे अनुपस्थित रहे। एक सूत्र ने कहा, "वे

अपना अलग एंजंडा चला रहे थे।" हाल ही में चड्ढा ने भारत में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठाकर सुर्खियां बटोरी थीं। उनका कहना था कि बच्चे के जन्म पर माता-पिता, दोनों को बधाई दी जाती है, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी मुख्यतः माता पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि पालन-पोषण की जिम्मेदारियां समान रूप से साझा होनी चाहिए। उन्होंने यह चीज कानूनों में भी प्रतिबिम्बित होने चाहिये। हवाई अड्डों पर महंगे खाने के खिलाफ उनकी पहल के चलते 'उड़ान यात्री कैफे' जैसे किफायती फूड काउंटर शुरू किए गए, जिससे यात्रियों को सस्ता खाना मिल सके। इसे उपभोक्ता अधिकारों की जीत बताया गया है। सुत्रों के अनुसार, पार्टी के इस फैसले से नाराज चड्ढा भाजपा नेतृत्व के संपर्क में हैं और उनके भगवा दल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
एडवोकेट पीवी सुरेश ने दलील देते हुए कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे और उनके अधिकारों को संरक्षित रखे।

खंडपीठ ने उनकी अपीलों पर पक्षकारों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में भर्ती परीक्षा होने से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अजीत शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भर्ती की सभी जरूरी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में इस स्तर पर भर्ती परीक्षा स्थगित करने से अत्यवस्था पैदा होगी। इसलिए भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं की जाए।

'5037 बीघा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मकान तोड़ने की नौबत आ जायेगी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पी सी भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार को और हाउसिंग बोर्ड को अपनी जमीन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिये और इसी में राज्य सरकार का और आम जनता काहित है। उन्होंने कहा कि 5037 बीघा जमीन में से वह जमीन, जिस पर अतिक्रमण नहीं है, उसे बचाने का प्रयास राज्य सरकार को पूरी तरह से करना चाहिये। सुनवाई के दौरान अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ए.ए.जी.) से आश्वासन लिया कि राजस्थान सरकार व हाउसिंग बोर्ड सुनिश्चित करें कि उक्त भूखंड में शेष खुले स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होने दिये जायेंगे। अदालत ने आदेश दिये हैं कि हाउसिंग बोर्ड न्यायिककर्ता के चक्की पूरे क्षेत्र का विस्तृत मैप बनायें, जिसमें विवादित क्षेत्र और खुले क्षेत्रों को अच्छे से अंकित किया गया हो, ताकि अतिक्रमण होने से

बृद्धा से 80 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अपराध है। जिसमें कई स्तरों पर करीब ढाई दर्जन से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया है। जमानत याचिका में कहा गया था कि उसके खाते में पांच लाख रुपये आए थे और वह पीड़िता को दस लाख रुपये देकर राजीनामा कर रहा है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं अदालत में पेश होकर पीड़ित महिला ने कहा था कि उसे जानंच एजेंसी से नहीं दिला पा रही है और वह दबाव में राजीनामा कर रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अतः 27 मार्च को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।